भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 898
दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

इंडिया केम, 2024

898. श्री बसवराज बोम्मई:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री गणेश सिंह:
श्री विजय बघेल:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री मुकेश राजपूत:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री परषोत्तमभाई रुपाला:
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री खगेन मुर्मु:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री मितेश पटेल बकाभाई:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडिया केम 2024 के 13वें संस्करण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) ऑटोमोटिव, निर्माण और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों की आर्थिक वृद्धि में रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की भूमिका क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उत्पादन बढ़ाने और पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए रसायन उद्योग को समर्थन देने के लिए उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा तैयार की गई ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पेट्रोकेमिकल उत्पादन में अग्रणी राज्य का नाम क्या है और इसमें गुजरात की क्या भूमिका है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(**क**): रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने 17 से 19 अक्टूबर, 2024 के दौरान मुंबई में मेगा कार्यक्रम "इंडिया केम 2024", एक प्रदर्शनी सह सम्मेलन के 13वें संस्करण का आयोजन किया। इंडिया केम 2024 का मुख्य उद्देश्य तेजी से बढ़ते भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग द्वारा पेश किए जा रहे अवसरों और

इस क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए विभिन्न सरकारी पहलों को प्रदर्शित करना और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेशकों और अन्य हितधारकों को बातचीत करने और गठबंधन बनाने के लिए एक मंच प्रदान करना था। इस कार्यक्रम में "मेक इन इंडिया" पहल का समर्थन करने के लिए भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग में निवेश की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया। इसने भारत में विदेशी कंपनियों को सहयोग और व्यापार विस्तार के लिए एक मंच भी प्रदान किया।

इस कार्यक्रम में 49 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों सहित 172 प्रदर्शकों ने भाग लिया और 78 वैश्विक सीईओ, 135 वक्ता और 689 विदेशी प्रतिभागियों, 1,115 भारतीय प्रतिनिधियों और 8,720 व्यापारिक आगंतुकों ने भाग लिया। डाई, कृषि रसायन, पेट्रोरसायन के साथ-साथ प्रक्रिया, संयंत्र और मशीनरी पर क्षेत्र-विशिष्ट सत्र थे। इसके अलावा, भारत-यूरोपीय संघ, भारत-पूर्वी एशिया, भारत-अमेरिका और भारत-रूस रसायन और पेट्रोरसायन फोरम सहित क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रित समर्पित सत्र थे, जो इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में एक वैश्विक सीईओ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के उद्योग जगत के नेताओं ने भारतीय रसायन उद्योग के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की। नीदरलैंड इस संस्करण का भागीदार देश था, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित अनेक भारतीय राज्य भागीदार राज्यों के रूप में नजर आए। अपने तीसरे और अंतिम दिन, इस कार्यक्रम में एक आकर्षक जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी रसायन कंपनियाँ और सिपेट – केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्र शामिल हुए। जॉब फेयर के दौरान, कंपनियों ने विभिन्न भूमिकाओं के लिए उनके द्वारा आवश्यक कौशल विवरण पर प्रस्तुतियाँ दीं और छात्रों को संभावित कैरियर संभावनाओं का पता लगाने के लिए उद्योग के साथ बातचीत करने का अवसर मिला।

(ख) : रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र आवश्यक सामग्री, उत्पाद और प्रौद्योगिकियां प्रदान करके ऑटोमोटिव, निर्माण और स्वास्थ्य सेवा जैसे उद्योगों की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ऑटोमोटिव उद्योग भारत में रसायनों और पेट्रोरसायनों के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। पॉलिमर, प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर जैसे पेट्रोरसायन बम्पर, डैशबोर्ड, सीट और टायर जैसे ऑटोमोटिव घटकों के विनिर्माण के लिए आवश्यक हैं। पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी), पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) और पॉलीयुरेथेन (पीयू) जैसी सामग्रियों का व्यापक रूप से वाहन उत्पादन में उपयोग किया जाता है। वाहनों के समुचित संचालन के लिए स्नेहक और मोटर तेल जैसे परिष्कृत पेट्रोरसायन उत्पाद महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, ईंधन एडिटिव्स इंजन की दक्षता और उत्सर्जन नियंत्रण में सुधार करते हैं। निर्माण कार्य में, रसायन एडहीसिव्स, पेंट और इन्सुलेशन सामग्री जैसी सामग्रियों के उत्पादन में योगदान देते हैं, साथ ही उच्च प्रदर्शन वाले पॉलिमर और कोटिंग्स भवन के स्थायित्व और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र चिकित्सा उपकरणों, फार्मास्यूटिकल्स और डायग्नोस्टिक उपकरणों के उत्पादन के लिए रसायनों पर निर्भर है, जिसमें सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयव (एपीआई), सिरिंज जैसे चिकित्सा उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले पॉलिमर, स्टेरिलिजेशन सामग्री और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के लिए सामग्री शामिल हैं।

कुल मिलाकर, रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र इन उद्योगों की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है, जो तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास और संधारणीय प्रथाओं को आगे बढ़ाता है।

(**ग**) एवं (**घ**) : रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग इस क्षेत्र में निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग की सहायता के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। ये उपाय इस प्रकार हैं:

पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) : रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए विभाग ने पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति अधिसूचित की है। पीसीपीआईआर की अवधारणा विकास के क्लस्टर आधारित मॉडल के रूप में की गई है जिसमें कॉमन आधारभूत संरचना और सहायक सेवाएं शामिल हैं। दाहेज (गुजरात),

विशाखापत्तनम-काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) और पारादीप (ओडिशा) में तीन पीसीपीआईआर स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में, इन पीसीपीआईआर में 824 पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन और सहायक उद्योग कार्यरत हैं, जिनका संचयी निवेश 2,43,000 करोड़ रुपये है और इन क्षेत्रों ने 3.7 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा किया है।

प्लास्टिक पार्क: विभाग पेट्रोरसायन की नई योजना के तहत प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की योजना को कार्यान्वित करता है। यह योजना आवश्यक अत्याधुनिक आधारभूत संरचना और सक्षम सामान्य सुविधाओं के साथ जरूरत आधारित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वित करना है ताकि इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार पैदा करने में मदद मिल सके। इस योजना के तहत, भारत सरकार प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन राज्य सरकार को परियोजना लागत के 50% तक अनुदान सहायता प्रदान करती है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब तक 10 प्लास्टिक पार्क अनुमोदित किए गए हैं और ये कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

उत्कृष्टता केंद्र: रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार करना और पॉलिमर और प्लास्टिक के नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को अनुदान सहायता प्रदान करना है। इस योजना का जोर मौजूदा विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के साथ-साथ उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार पर है। इस योजना के तहत, भारत सरकार 5 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के अधीन कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक इस योजना के तहत 18 उत्कृष्टता केंद्र अनुमोदित किए गए हैं। पहले उत्कृष्टता केंद्र योजना केवल पेट्रोरसायन क्षेत्र के लिए उपलब्ध थी, अब संशोधित योजना में रसायन क्षेत्र को भी शामिल किया गया है।

रसायन संवर्धन विकास योजना (सीपीडीएस) : इस योजना का उद्देश्य अध्ययन, सर्वेक्षण, डेटा बैंक, प्रचार सामग्री के माध्यम से ज्ञान उत्पादों के निर्माण के माध्यम से रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के विकास और वृद्धि को सुविधाजनक बनाना है, साथ ही क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सेमिनार, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की सुविधा प्रदान करना भी है। यह योजना रसायन और पेट्रोरसायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों को पुरस्कृत करके अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा देती है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) : रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने उत्पाद मानकों को अनिवार्य बनाने की कवायद शुरू की है ताकि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत घरेलू विनिर्माता और विदेशी आपूर्तिकर्ता दोनों ही मानव, पशु या पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा, अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सार्वजनिक हित में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मापदंडों को पूरा कर सकें। तदनुसार, इन मानकों को अनिवार्य बनाने के लिए भारत के राजपत्र में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) अधिसूचित किए जा रहे हैं। अब तक, विभाग द्वारा 72 रसायनों और पेट्रोरसायनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं ।

नाम पद्धति कोड का नया हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएसएन) : रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने विभिन्न वस्तुओं में अंतर करने के लिए समर्पित एचएसएन कोड निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की है, ताकि विशेष रूप से इन रसायनों के आयात-निर्यात के लिए सही आंकड़े एकत्र किए जा सकें, जिससे ऐसे रसायनों के लिए शुल्क की अलग-अलग दरों जैसे लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप संभव हो सकें।

(ङ) : गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब पेट्रोरसायन उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। देश के कुल पेट्रोरसायन उत्पादन में इन 5 राज्यों का 84% हिस्सा है। पेट्रोरसायन उत्पादों का राज्यवार उत्पादन (वित्त वर्ष 2023-24) इस प्रकार है:

क्र. सं.	**राज्य**	***वित्त वर्ष* 2023-2024 के लिए *मात्रा (मीट्रिक टन में)***	**भारत में उत्पादन का % हिस्सा**
1	गुजरात	23387025	55.5%
2	हरयाणा	4130203	9.8%
3	पश्चिम बंगाल	3699393	8.8%
4	महाराष्ट्र	2433411	5.8%
5	पंजाब	1731626	4.1%
7	अन्य राज्य	6753911	16%
कुल		42135569	100%
टिप्पणी : उत्पादन संबंधी आंकड़े बड़े और मध्यम श्रेणी के पेट्रोरसायन उद्योगों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित हैं।			

उपरोक्त तालिका से यह पता चलता है कि गुजरात देश में पेट्रोरसायन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, देश के कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 55.5% है, जिसमें रणनीतिक रूप से स्थित पोर्टों सहित उन्नत आधारभूत संरचना और सामान्य उपयोगिताओं सहित एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है।

*****